भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 396*

28 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नौकरियां"

***396. श्री रविन्दर कुशवाहा:**

श्री रवि किशन:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कितनी नौकरियों का सृजन हुआ है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कितनी नौकरियों का सृजन होने की संभावना है; और

(ग) ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

भारी उद्योग मंत्री

(डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

<u>विवरण</u>

"ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नौकरियां" विषय पर लोकसभा में 28.03.2023 को उत्तर के लिए नियत श्री रविन्दर कुशवाहा और श्री रवि किशन के तारांकित प्रश्न संख्या 396 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): यह आँकड़ा भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता। तथापि, *सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबिल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम)* से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऑटोमोबिल क्षेत्र में 2018-19 में 2.83 करोड़ नौकरियां (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) तथा 2019-20 में 3.07 करोड़ नौकरियां (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) उपलब्ध कराई गईं। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 का कोई आँकड़ा सियाम के पास उपलब्ध नहीं है।

इस क्षेत्र में अगले 3 वर्षों के दौरान रोज़गार सृजन की संभावना के संबंध में, सियाम ने सूचित किया है कि यह आंकड़ा कई कारकों पर निर्भर करेगा जिनमें बाज़ार का रुख़, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी उद्भव आदि शामिल हैं जिनके लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ऑटोमोबिल और ऑटो घटक के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को प्रशासित कर रहा है जिससे 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27) की अवधि में 7.5 लाख से अधिक रोज़गार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित होने का अनुमान है।

(ग): ऑटोमोबिल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय निम्नलिखित तीन स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है:

(i) सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम वर्ष 2015 में शुरु की और वर्तमान में फेम इंडिया स्कीम का चरण-।। दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके लिए कुल बजटीय सहायता 10,000 करोड़ रूपये है। फेम-।। के इस चरण में, सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सब्सिडी के माध्यम से 7,090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55,000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहियों के लिए सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्कीम का ब्यौरा http://fame2.heavyindustries.gov.in/index.aspx पर उपलब्ध है।

(ii): सरकार ने देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए 12 मई,2021 को उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को अनुमोदित किया ताकि उनके विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। इस स्कीम का कुल बजटीय परिव्यय 18,100 करोड़ रुपये है। इस स्कीम में 50 गीगावाट घंटे की संचयी एसीसी बैटरी विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। स्कीम का ब्यौरा https://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=2487 पर उपलब्ध है।

(iii): ऑटोमोबिल उद्योग को ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक विषयक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के अंतर्गत भी आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है जिसे 5 वर्ष की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रूपए के बजट परिव्यय से 15 सितंबर,2021 को अनुमोदित किया गया है। पीएलआई ऑटो स्कीम का ब्यौरा भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट https://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=2482 पर उपलब्ध है।

****